नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 024
दि. 24.05.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

श्रमिकों का सम्मान और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता : योगी आदित्यनाथ

(जीएनएस)।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों को राज्य की प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए शनिवार को कहा कि उन्हें सम्मान तथा सुरक्षा देना सरकार की प्राथमिकता है।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और रोजगार सृजन को अधिक प्रभावी तथा व्यापक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने 'बाल श्रमिक विद्या योजना' को प्रदेश के सभी 75 जिलों तक विस्तार देने, 'सेवामित्र व्यवस्था' को और मजबूत बनाने, बड़े शहरों में निर्माण श्रमिकों के लिए आधुनिक सुविधा केंद्र विकसित करने तथा रोजगार मिशन को वैश्विक अवसरों से जोड़ने के निर्देश दिए।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास की सबसे बड़ी ताकत हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी बच्चा आर्थिक मजबूरी के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए।

उन्होंने बाल श्रम प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही निजी क्षेत्र के सहयोग से इन बच्चों के कौशल विकास की कार्ययोजना तैयार करने को भी कहा। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020 में शुरू की गई 'बाल श्रमिक विद्या योजना' के तहत आठ से 18 वर्ष आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसमें कहा गया कि वर्तमान में यह योजना 20 जिलों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने इसे नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जिलों में लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 'सेवामित्र व्यवस्था' को रोजगार और जनसुविधा का अभिनव मॉडल बताया और इसे अधिक प्रभावी तथा जनोपयोगी बनाने पर जोर दिया।

पीएम मोदी को अमेरिका का न्योता, मार्को रूबियो ने पहुंचाया ट्रंप का संदेश! प्रधानमंत्री ने इन 3 लाइनों में समझाया

नई दिल्लीः ईरान के साथ जंग में अमेरिका की किरकिरी होने के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस समय भारत के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया। वैश्विक उथल-पुथल के बीच इस बेहद अहम मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने मीटिंग की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं। पीएम मोदी ने 3 लाइनों में अमेरिका और भारत के रिश्तों के महत्व को समझा दिया। पीएम मोदी ने लिखीं ये 3 लाइन? भारत-अमेरिका की व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में निरंतर प्रगति को लेकर बातचीत हुई। क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के साथ-साथ सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी हमारे बीच चर्चा हुई। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। सर्जियो गोर भी हुए मीटिंग में शामिल चार दिवसीय दौरे पर भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के राजदूत सर्जियो गोर भी शामिल हुए।

मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से की मुलाकात, प्रधानमंत्री बोले- 'वैश्विक हित में मिलकर काम करेंगे भारत और अमेरिका'

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। पीएम मोदी ने कहा, 'भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।'

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मार्को रूबियो के साथ फोटो शेयर की हैं। पीएम मोदी ने फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, 'वर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का स्वागत करके मुझे खुशी हुई।'

पीएम मोदी ने मार्को रूबियो से हुई मुलाकात के बारे में बताते हुए एक्स पर लिखा, 'हमने भारत-वर व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।'

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा, 'भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।'

ढट मोदी और विदेश मंत्री रूबियो के बीच हुई इस बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और अमेरिकी उप विदेश मंत्री एलिसन हुकर मौजूद थे।

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इस बैठक को सार्थक बताते हुए एक्स पर लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में मार्को रूबियो के साथ शामिल होना बहुत अच्छा लगा। हमने सुरक्षा, व्यापार और अहम टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में अमेरिका-भारत सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर सार्थक चर्चा की।'

अमेरिकी राजदूत ने भारत को अहम साझीदार बताते हुए आगे लिखा, 'ये ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारे दोनों देशों को मजबूत बनाते हैं और एक स्वतंत्र व खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं। भारत, अमेरिका का एक अहम साझीदार है।'

अमेरिकी राजदूत के अनुसार, आगामी मुलाकातों का मुख्य उद्देश्य प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना होगा। इनमें रक्षा साझेदारी, उन्नत टेक्नोलॉजी, व्यापारिक संबंध और Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) के तहत आपसी सहयोग शामिल हैं।

19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए गए; पीएम मोदी ने नव नियुक्त युवाओं को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित किया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर में भर्ती हुए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। देशभर में एक साथ 47 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेला भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और नागरिक-केंद्रित शासन को मजबूत करना है। नव नियुक्त उम्मीदवारों ने रेलवे, इसरो, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग सहित प्रमुख मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभाला। 19वें रोजगार मेले के अंतर्गत हुई नियुक्तियों में से 50 प्रतिशत से अधिक नियुक्तियां भारतीय रेलवे के बढ़ते क्षेत्रों के लिए समर्पित थीं।

नव नियुक्त युवाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें और उनके परिवारों को बधाई दी और इस अवसर को हजारों परिवारों के जीवन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि नव नियुक्त युवा राष्ट्र के विकास पथ में जिम्मेदार और महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं और '2047 तक विकसित भारत' के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगे। समर्पित लोक सेवा के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने नियुक्त युवाओं को याद दिलाया कि सरकारी नौकरी को केवल एक पद के रूप में नहीं, बल्कि नागरिकों के जीवन को सरल बनाने और राष्ट्रीय प्रगति में सार्थक योगदान देने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने उनसे "नागरिक देवो भव" के मार्गदर्शक सिद्धांत का पालन करने का आग्रह किया और इस बात पर बल दिया कि नागरिक कल्याण शासन के केंद्र में होना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और भारतीय युवाओं की क्षमताओं तथा देश की तकनीकी प्रगति में बढ़ते अंतरराष्ट्रीय विश्वास पर प्रकाश डाला।

गर्मी का तांडव जारी, 46.4त्ड पहुंचा बांदा का तापमान, आईएमडी ने इन राज्यों के लिए जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट

देश के बड़े हिस्से इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं, कई राज्यों में 40 से 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश सहित कई क्षेत्रों के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में लू की स्थिति लगातार बनी हुई है।

'माता-पिता आईएएस, फिर भी आरक्षण?' क्रीमी लेयर रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए तीखे सवाल, क्या है पूरा मामला

(जीएनएस)।

देश में आरक्षण व्यवस्था को लेकर दशकों से चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ऐसा सवाल उठाया है, जिसने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है।

अदालत ने पूछा है कि अगर किसी परिवार ने आरक्षण का लाभ लेकर सामाजिक और आर्थिक रूप से पर्याप्त उन्नति कर ली है, तो क्या अगली पीढ़ी को भी उसी तरह आरक्षण का लाभ मिलता रहना चाहिए? सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की टिप्पणी-"अगर माता-पिता दोनों क्लास अधिकारी हैं, तो उन्हें आरक्षण क्यों मिलना चाहिए?"-अब इस बहस का केंद्र बन गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना है। लेकिन जब कोई परिवार शिक्षा, नौकरी और आर्थिक स्थिति में काफी आगे बढ़ चुका हो, तब अगली पीढ़ी को भी वही लाभ देना न्यायसंगत है या नहीं, इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ सामाजिक गतिशीलता भी आती है। ऐसे में यदि हर पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेती रहेगी, तो यह व्यवस्था कभी अपने वास्तविक उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएगी।

यह मामला कर्नाटक के कुरुबा समुदाय से जुड़े एक उम्मीदवार का है, जिसे ओबीसी श्रेणी के तहत सहायक अभियंता पद पर चयन मिला था। हालांकि जिला जाति एवं आय सत्यापन समिति ने उसे 'क्रीमी लेयर' में मानते हुए जाति वैधता प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया।

समिति ने पाया कि उम्मीदवार के माता-पिता दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और परिवार की वार्षिक आय करीब 19.48 लाख रुपये है, जो निर्धारित सीमा से अधिक है। इसी आधार पर उसे आरक्षण लाभ के लिए अयोग्य माना गया।

उम्मीदवार की ओर से पेश अधिवक्ता शशांक रत्नू ने अदालत में दलील दी कि केवल वेतन आय के आधार पर किसी को क्रीमी लेयर नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि मौजूदा नियमों में सरकारी कर्मचारियों की स्थिति-जैसे वे ग्रुप 'अ' या 'इ' सेवा में हैं-ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि केवल वेतन आय को आधार बनाया गया, तो महंगाई और वेतन संरचना के कारण चपरासी, ड्राइवर और क्लर्क जैसे निचले स्तर के कर्मचारी भी आरक्षण से बाहर हो सकते हैं, जबकि वे सामाजिक रूप से अब भी पिछड़े हो सकते हैं।

'सामाजिक उन्नति के बाद भी क्यों चाहिए आरक्षण?'

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिए कि आर्थिक और शैक्षिक उन्नति का सामाजिक स्थिति पर असर पड़ता है। अदालत ने कहा कि यदि माता-पिता पहले ही आरक्षण का लाभ लेकर उच्च पदों और बेहतर जीवन स्तर तक पहुंच चुके हैं, तो अगली पीढ़ी को उसी आधार पर लगातार लाभ देना पुनर्विचार का विषय है।

पीठ ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था में संतुलन जरूरी है, ताकि इसका लाभ वास्तव में जरूरतमंद और अब भी पिछड़े वर्गों तक पहुंच सके।

यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब सुप्रीम कोर्ट में एससी/एसटी वर्गों के भीतर भी 'क्रीमी लेयर' लागू करने को लेकर बहस तेज हो चुकी है।

अगस्त 2024 में सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की थी। हालांकि केंद्र सरकार ने बाद में साफ किया था कि फिलहाल एससी/एसटी वर्गों में क्रीमी लेयर लागू करने का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है।

अमेरिका फर्स्ट वीसा शेड्यूलिंक क्या है? अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारतीय को दिया 'रिटर्न गिफ्ट'

(जीएनएस)।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो भारत दौरे पर हैं। दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि, अमेरिका भारतीय बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए नया 'अमेरिका फर्स्ट वीजा शेड्यूलिंग टूल' ?शुरू करने जा रहा है।

उन्होंने इसे भारत-अमेरिका रिश्तों को और मजबूत करने वाला कदम बताया। रुबियो ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की दोस्ती का भी जिक्र किया। माना जा रहा है कि इस नए सिस्टम से भारतीय प्रोफेशनल्स को अमेरिकी वीजा प्रक्रिया में बड़ी राहत मिल सकती है। साथ ही रुबियो ने क्वाड और इंडो-पैसिफिक रणनीति में भारत की अहम भूमिका पर भी जोर दिया। मार्को रुबियो के मुताबिक यह नया टूल खास तौर पर बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद वीजा इंटरव्यू और अपॉइंटमेंट प्रक्रिया को ज्यादा तेज और आसान बनाना है। अमेरिका मानता है कि बिजनेस, टेक्नोलॉजी और निवेश से जुड़े लोग भारत-अमेरिका रिश्तों को मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को प्राथमिकता देकर उनकी यात्रा और कामकाज को आसान बनाने क ी कोशिश की जा रही है।

किन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

रुबियो ने साफ किया कि यह बदलाव हर वीजा आवेदक के लिए नहीं होगा। इसका फायदा मुख्य रूप से बिजनेस प्रोफेशनल्स, निवेशकों, टेक एक्सपर्ट्स और उन लोगों को मिल सकता है जो भारत और अमेरिका के आर्थिक रिश्तों में अहम भूमिका निभाते हैं। माना जा रहा है कि इससे दोनों देशों के बीच बिजनेस ट्रैवल और कॉरपोरेट सहयोग बढ़ेगा। लंबे इंतजार और अपॉइंटमेंट की परेशानी से भी कुछ हद तक राहत मिल सकती है।

मोदी-ट्रंप रिश्तों का भी किया जिक्र

अपने बयान में रुबियो ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के रिश्तों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच मजबूत समझ और भरोसा है, जिसका असर भारत-अमेरिका साझेदारी पर भी दिखाई देता है। अमेरिका भारत को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अहम साझेदार मानता है और दोनों देशों के बीच लगातार रणनीतिक सहयोग बढ़ रहा है।

अजय राय की पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी, बीजेवी नेताओं की आ गई प्रतिक्रिया, बोले-ऐसे लोगों को भेजो जेल

(जीएनएस)।

लखनऊः कांग्रेस नेता अजय राय की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कथित अभद्र भाषा के प्रयोग से राजनीतिक माहौल तनावपूर्ण हो गया है। भाजपा नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

यूपी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा, "प्रशासन को ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं और किसी को भी कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। हर चीज की एक सीमा होती है - चाहे वह पलटवार हो, विरोध हो या अपने विचार व्यक्त करने की आजादी हो। हर किसी को बोलने की आजादी है, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। हालांकि, भाषा की गरिमा को तार-तार करना और इस तरह की टिप्पणियां करना कभी भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।"

बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत ने बोला हमला

इसी मुद्दे पर भाजपा विधायक कैलाश राजपूत ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, "इससे पहले, राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर

आए थे। उन्होंने भी देश के सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। कांग्रेस नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।"

उन्होंने कहा, "शुरूआत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ही देश के प्रधानमंत्री रहे थे। ये लोग इसी सोच के साथ बड़े हुए हैं कि प्रधानमंत्री का पद केवल उनके परिवार के लिए ही आरक्षित है। इसलिए, जब राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बिगड़ा, तो उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वे इसी तरह का दुर्व्यवहार जारी रखते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता राहुल को उत्तर प्रदेश में घुसने भी नहीं देगी और अजय राय को जल्द ही एहसास हो जाएगा कि उन्हें किन परिणामों का सामना करना पड़ेगा।"

गौरव वल्लभ ने प्रतिक्रिया दी

बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, "किसी भी विपक्षी दल का नेता, यहां तक कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस का कोई छोटा-मोटा नेता भी, देश के प्रधानमंत्री के लिए इतने निचले स्तर के, घटिया, अभद्र और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

मुख्यमंत्री योगी की घोषणा, देवरिया में सोनूघाट-बरहज फोरलेन सड़क का निर्माण जल्द

(जीएनएस)।

देवरिया। जिले में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोनूघाट-बरहज मार्ग का कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया गया है। यह सुनकर उमड़ी जनता ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम के आश्वासन के बाद लोगों को उम्मीद जगी है कि अब जल्द ही इस मार्ग का निर्माण शुरू होगा।

दरअसल, सोनूघाट-बरहज फोरलेन निर्माण की स्वीकृति शासन से कई माह पहले ही मिल चुकी थी। शासन ने इसके निर्माण के लिए 172 करोड़ 25 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी। साथ ही पहली किस्त के रूप में 10 करोड़ रुपये भी जारी कर दिए गए थे। लोक निर्माण विभाग ने टेंडर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली थी, लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका।

सूत्रों के अनुसार, सड़क निर्माण के लिए मिली 10 करोड़ की पहली किस्त को बिजली विभाग को देकर विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराई गई, जिससे सड़क का काम लटक गया।

बरहज से सोनूघाट के बीच की दूरी 21.750 किलोमीटर है। वर्तमान में इसकी चौड़ाई सात मीटर है। अब इसे फोरलेन बनाया जाएगा।

प्रत्येक लेन की चौड़ाई सात मीटर होगी और दोनों लेन के बीच दो मीटर का डिवाइडर बनाया जाएगा। क्षेत्रवासी लंबे समय से इस मार्ग के चौड़ीकरण की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद अब क्षेत्र की जनता ने राहत की सांस ली है। लोगों को भरोसा है कि जल्द ही इस मार्ग का निर्माण शुरू होगा और आवागमन सुगम हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने पिछली बार 29 अप्रैल को देसही ब्लाक के पड़ियापार में आयोजित लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम में 501 परियोजनाओं पर करीब सात अरब रुपये की सौगात दी थी। इसके एक साथ बाद ही शुक्रवार को पथरदेवा, रामपुर कारखाना व सदर ब्लाक में 19 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। जिस पर 655.45 करोड़ रुपये लागत आई है।

मुख्यमंत्री ने सात विधानसभा में केवल तीन विधानसभा से जुड़े कार्य होने पर उन्होंने लोगों को जरूरत के हिसाब से आवश्यक कार्यों को पूरा करने का विश्वास दिलाया। जिसमें सोनूघाट-बरहज की सड़क का भी जल्द निर्माण कार्य कराए जाने की बात दोहराई।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने देवरिया से काफी अधिक लगाव होने की बात कही। मुख्यमंत्री के भाषण के पूर्व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि योगी जी इसके पहले 29 अप्रैल को देवरिया आए तो सात अरब का सौगात दे गए। उन्होंने कहा कि ऐसे महान व्यक्ति का इस धरती पर बारंबार स्वागत है। वे ऐसे ही सौगात लेकर बार-बार आए ताकि क्षेत्र व जनपद का विकास हो सके।

किस मंत्रालय का कैसा रहा काम, किसका परफॉर्मेंस बेस्ट? मोदी सरकार ने पहली बार बनाई मंत्रियों के कामकाज की रिपोर्ट

(जीएनएस)।

करीब साढ़े चार घंटे चली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों और अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि शासन में सुस्ती और फाइलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों की जिंदगी को आसान बनाना होना चाहिए और हर योजना का लाभ तेजी से जनता तक पहुंचना चाहिए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार मंत्रालयों और विभागों के कामकाज का विस्तृत मूल्यांकन किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार मंत्रालयों और विभागों के कामकाज का विस्तृत मूल्यांकन किया है. इस विशेष समीक्षा में फाइलों के निपटारे की रफ्तार, जनता की शिकायतों के समाधान, कैबिनेट नोट्स पर समय पर जवाब और प्रशासनिक कार्यकुशलता जैसे कई अहम पैमानों पर मंत्रालयों का प्रदर्शन परखा गया.

बताया जा रहा है कि यह अभ्यास सरकार के भीतर जवाबदेही बढ़ाने और फैसलों की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से किया गया. कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रालयों के प्रदर्शन की रिपोर्ट पेश की.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, करीब साढ़े चार घंटे चली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों और अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि शासन में सुस्ती और फाइलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों की जिंदगी को आसान बनाना होना चाहिए और हर योजना का लाभ तेजी से जनता तक पहुंचना चाहिए.

रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया, अलग-अलग मानकों पर मंत्रालयों का आकलन किया गया, हालांकि सभी पैरामीटर को जोड़कर कोई एक ओवरऑल रैंकिंग जारी नहीं की गई. रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता मामले मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, बिजली मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय कई श्रेणियों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विभागों में शामिल रहे.

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने जन शिकायत निवारण और पश्चिम एशिया संकट से जुड़े प्रबंधन में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया. वहीं कोयला मंत्रालय को फाइल निपटान और प्रशासनिक प्रबंधन के मामले में सबसे अधिक अंक मिले. बिजली और स्वास्थ्य मंत्रालयों को भी प्रभावी कामकाज के लिए सराहा गया.

बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने 'विकसित भारत 2047' के विजन को दोहराते हुए कहा कि यह केवल नारा नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता है. उन्होंने कहा कि मंत्रालयों को कम समय में अधिक परिणाम देने होंगे और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा.

सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट सचिव की प्रस्तुति के बाद कई मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें भी शुरू कर दी हैं. टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक में अधिकारियों से कहा कि किसानों और गरीबों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक दिक्कतों का सामना नहीं करना चाहिए. उन्होंने जन शिकायतों के त्वरित समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया.

सरकार का मानना है कि इस तरह की नियमित समीक्षा से मंत्रालयों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और आम लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ जल्दी मिल सकेगा.

ओलंपियाडः सीएम योगी ने किया विजेताओं का सम्मान; उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी किया सम्मानित, ये अतिथि रहे मौजूद

(जीएनएस)।

नई दिल्ली , अमर उजाला की ओर से गत वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ओलंपियाड परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें देशभर के लाखों छात्रों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कक्षा 3 से 12 तक के विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नेशनल रैंक-1 के विजेताओं को सम्मानित करने का सिलसिला जारी है।

अमर उजाला की ओर से गत वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ओलंपियाड परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें देशभर के लाखों छात्रों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में कक्षा 3 से 12 तक के विभिन्न विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नेशनल रैंक-1 के विजेताओं को सम्मानित करने का सिलसिला जारी है।

18 मई 2026 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। इसी कड़ी में 19 मई 2026 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल तथा उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ में नेशनल रैंक-1 के विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इससे पहले 17 मई 2026 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित समारोह में उत्तराखंड राज्य से चयनित नेशनल रैंक-1 के विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इन मेधावियों को 21,000 रुपये नकद, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए।

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय टॉपर्स को भी भविष्य में आयोजित कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाएगा, जिसकी जानकारी अमर उजाला टीम द्वारा उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर साझा की जाएगी। अमर उजाला नेशनल ओलंपियाड-2026झ27 के विद्यार्थियों के लिए पुनः पंजीकरण शुरू हो चुका है। इस वर्ष ओलंपियाड में कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए इंगलिश, मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिरंग, हिंदी और टेक एंड एआई विषयों के लिए पंजीकरण खुले हैं।

पुरस्कृत : विद्यार्थी

सोहम कार्तिकेयन गोयल	दिल्ली पब्लिक स्कूल, रानीपुर	अरीन खान	लीड कन्वेंट स्कूल
समर टोपनो	डीपीएस रानीपुर	अभिलाषा सिंह	पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय, जनकपुरी
अनुरुद्ध नेगी	डीएवी पब्लिक स्कूल	आयुष कुमार गौर	बीआरएस कन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल
विशेष दसलिया	ऑरम द ग्लोबल स्कूल	मणिककर्णिका राठौर	वेदान विनायक इंटरनेशनल स्कूल
कुशी	दून कैम्ब्रिज स्कूल	वंश मोदी	श्री गुलाब राय मोंटेसरी सीनियर स्कूल
वंश बिष्ट	सेंट थेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल	अनन्या श्रीवास्तव	गीता देवी सरस्वती बाल शिक्षण संस्थान
कुशाग्र जोशी	ऑरम द ग्लोबल स्कूल	जतिन अग्रवाल	सीएफ एंड्रूज स्कूल
निर्मय प्रताप सिंह	चिल्ड्रन्स अकादमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल	रासांश रवि	आशा मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल
वेद रंजन यादव	सेंट जॉन्स स्कूल	मानवी अग्रवाल	बालूनी पब्लिक स्कूल
शौर्य मिश्रा	पीटीएल क्राइस्ट अकादमी, खटूरा	अंशिका सिंह	इन्वेंटर पब्लिक स्कूल
सान्वी गुप्ता	सेंट जोसेफ एसआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल	दक्ष विनोद अग्रवाल	विश्वा भारती पब्लिक स्कूल
हर्षवर्धन जयन	रेनबो स्कूल	अस्मी श्रीवास्तव	जीएम अकादमी
आयुष निषाद	एसडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल	ख्याति सिंह	सेंट क्लेर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल
आदित्य श्योरन	लॉर्ड कृष्णा इंटर कॉलेज	मानशी यादव	न्यू टाउन हॉल पब्लिक स्कूल / कॉलेज
अरुष बंसल	डीपीएस, गाजियाबाद मेरठ रोड	पूजा	एन एस डी एस विद्या मंदिर
ऑद्विक मिश्रा	जेबी अकादमी, अयोध्या	गुरमीत सिंह	एएसएम मॉडर्न अकादमी
समर चौबे	एसडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल	सान्या	एक्मे ग्लोबल स्कूल
अमोघ गुप्ता	सेंट थेरेसा स्कूल	जितेंद्र कुमार	डीकेएसएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल
राघव सिंह गौतम	सेंट विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल	अर्पिता शुक्ला	कर्मयोगी विद्या निकेतन इंटर कॉलेज
रिदान शेफर्ड	आदर्श विद्यालय कंपोजिट, उरुला	प्रिया मौर्य	पंडित राम अवध स्मार्ट इंटर कॉलेज
तनुज पटेल	सेक्रेड हार्ट किजुकेशन-2		

सीएम योगी बोलेः राजस्व मुकदमों में देरी पर तय होगी अफसरों की जवाबदेही, दाखिल-खारिज में यह जिले सबसे कमजोर

(जीएनएस)।

लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्व मामलों का सही निपटारा शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। भूमि और राजस्व से जुड़े विवाद सामाजिक सौहार्द से सीधे जुड़े होते हैं, इसलिए इन मामलों में देरी स्वीकार्य नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित समय-सीमा के बाद भी लंबित रहने वाले मामलों में संबंधित अधिकारियों और कार्मिकों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने शनिवार को राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण की प्रगति की उच्चस्तरीय समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व न्यायालयों की कार्यक्षमता को और अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि आम नागरिक को शीघ्र न्याय मिल सके। निर्धारित समय सीमा से अधिक लंबित मुकदमों का अभियान चलाकर निस्तारण किया जाए।

सीएम ने कहा कि तहसील और जनपद स्तर पर नियमित समीक्षा हो और कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलों की जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली केवल आंकड़ों तक सीमित न रहे, बल्कि आम लोगों को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए।

भू उपयोग परिवर्तन में अमेठी समेत कई जिले पीछे

बैठक में बताया गया कि

आरसीसीएमएस पोर्टल के माध्यम से धारा-80 (भू-उपयोग परिवर्तन) के अंतर्गत लंबित वादों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। 1 जनवरी को कुल 85158 वाद लंबित थे, जिनमें से 77578 का निस्तारण किया गया था। वहीं 22 मई तक कुल लंबित वादों की संख्या घटकर 38166 रह गई, जिनमें 29543 वादों का निस्तारण किया गया। धारा-80 के मामलों में बस्ती, चित्रकूट, अयोध्या, बागपत और कन्नौज ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि मेरठ, वाराणसी, अमेठी, गौतमबुद्धनगर और हापुड़ का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया।

दाखिल खारिज में रामपुर-मुरादाबाद का प्रदर्शन कमजोर

बैठक में बताया गया कि धारा-34 (दाखिल खारिज) के अंतर्गत लंबित वादों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है। 1 जनवरी 2026 को कुल 2244466 वाद लंबित थे, जो 22 मई तक घटकर 1059139 रह गए। इस अवधि में 540945 वादों का निस्तारण किया गया। समीक्षा में बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ और बदायूं का प्रदर्शन बेहतर पाया गया, जबकि गोरखपुर, संतकबीरनगर, प्रतापगढ़, बलिया और देवरिया अपेक्षित प्रगति नहीं कर सके।

पैमाइश में लखनऊ-अमेठी, कुर्रा बंटवारे में प्रतापगढ़-गोंडा पीछे

धारा-33 के अंतर्गत निर्विवादित वरासत के मामलों में 2025 में कुल 1689732 आवेदन मिले थे, जिनमें से 1643104 का निस्तारण किया गया। वहीं 22 मई तक प्राप्त 715872 आवेदनों में से 652512 का निस्तारण किया जा चुका है। धारा-24 (पैमाइश) के मामलों में गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, प्रतापगढ़, अमेठी और मुजफ्फरनगर अपेक्षित प्रगति नहीं कर सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में प्रगति संतोषजनक नहीं है, वहां वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। धारा-116 (कुर्रा बंटवारा) में वाराणसी, एटा, आजमगढ़, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज का प्रदर्शन बेहतर रहा, जबकि प्रतापगढ़, मुजफ्फरनगर, कानपुर नगर, गोंडा और बलिया का प्रदर्शन कमजोर पाया गया।

यीडा में 17 निवेशकों को भूमि आवंटन, सीएम योगी बोले- यूपी बना देश की इकॉनमी का ब्रेकथ्रू

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र के अंतर्गत 17 निवेशकों को शुक्रवार को भूमि आवंटन पत्र प्रदान किए. निवेशकों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी ने अब टूरिज्म, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट के विश्वस्तरीय डेस्टिनेशन के रूप में खुद को स्थापित किया है. अपने उत्तर प्रदेश के ब्रांड एंबेसडर के रूप में प्रदेश की नई छवि को देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है. यूपी में निवेश करने वाले निवेशक प्रदेश के विकास में सरकार के सहयात्री हैं.

सीएम योगी ने कहा कि हम लोगों ने जिस जेवर क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है और जिस क्षेत्र में आपको अलाटमेंट लेटर वितरित किए गए हैं, आज से 9 वर्ष पहले यह भारत का सबसे डरावना क्षेत्र हुआ करता था. वहां गंभीर आपराधिक घटनाएं होती थीं. शाम पांच-साढ़े पांच बजे के बाद आवागमन बंद हो जाता था.लाइफ सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही हुआ करती थी. इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, लेकिन आज जेवर, यीडा क्षेत्र में जो परिवर्तन दिख रहा है, वह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, और यही हाल यूपी के हर जनपद का है.

यूपी में आर्म्स लाइसेंस रिपोर्ट पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, बोले- 'अदृश्य शस्त्र' ज्यादा खतरनाक

2017 के पहले माफिया को वितरित किए गए थे जनपद

सीएम ने कहा कि 2017 के पहले सत्ता के सामानांतर माफिया का साम्राज्य हुआ करता था. हर जनपद में भय व दहशत का माहौल था. महिलाएं बाजार या रोजगार के लिए बाहर जाती थीं तो परिवार की चिंता होती थी कि वे सूर्यास्त के पहले वापस आ जाएं. व्यापारी 6 बजे के पहले प्रतिष्ठान बंद करने पर मजबूर थे. सड़कें गड्ढों से भरी थीं. कनेक्टिविटी, बिजली की हालत बुरी थी. मुश्किल से 4-5 घंटे बिजली मिल जाए तो लोग खुद को भाग्यशाली मानते थे. हर माफिया को अलग-अलग जनपद वितरित किए गए थे. माफिया व आपराधिक गिरोह के लोग जनपद व थाने का संचालन करते थे. सरकार के पास नीति, नीयत, सुरक्षा व लैंडबैंक भी नहीं था.

चारधाम यात्रा को लेकर स्वामी अरुण गिरी की श्रद्धालुओं को नसीहत, यात्रा पिकनिक नहीं

विकास की पहली शर्त है सुरक्षा

सुरक्षा को विकास की पहली शर्त बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए अनुकूल वातावरण बनाना पड़ता है. असुरक्षित वातावरण में कुछ भी नहीं हो सकता.आज यूपी में बिना रोकटोक, बिना लेनदेन, उद्योग-व्यापार अनुकूल नीतियों के लाभ दिखाई दे रहे हैं। अब यूपी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बढ़िया है। देश में यदि प्रतिस्पर्धा हो तो यूपी टॉप राज्यों में होगा। एक्सप्रेसवे का 60 प्रतिशत हिस्सा और चार लाख किमी. का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यूपी के पास है. हर जिला मुख्यालय फोर-लेन, तहसील या ब्लाक मुख्यालय फोर-लेन/टू-लेन से जुड़ा है. यूपी की एयरकनेक्टिविटी सबसे अच्छी है. 2017 से पहले यूपी में डेढ़ एक्सप्रेसवे, दो एयरपोर्ट संचालित थे. आज 16 एयरपोर्ट संचालित हैं, उसमें से पांच अंतरराष्ट्रीय हैं. छह एयरपोर्ट पर हम काम कर रहे हैं, एयरक्राफ्ट मिल जाएं तो इन्हें भी बहुत जल्द संचालित करेंगे.

निवेश के स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध

निवेशकों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी के पास 16 हजार किमी. का रेल कॉरिडोर है. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईस्टर्न/वेस्टर्न) का जंक्शन भी यूपी में है. जिस क्षेत्र में आपका निवेश हो रहा है, वहां रोड, फ्रेट कॉरिडोर, विश्व स्तरीय एयर कनेक्टिविटी भी है. वह क्षेत्र लाजिस्टिक हब बनने जा रहा है. यूपी के पास पहली रैपिड रेल, पहला इनलैंड वाटरवे (वाराणसी से हल्दिया) संचालित है। पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने यूपी में लंबी छलांग लगाई है. सात शहरो में मेट्रो का संचालन हो रहा है.

यूपी अब माफिया, गुंडा, कर्फ्यू, अराजकता, दंगा मुक्त

सीएम योगी ने कहा कि यूपी अब माफिया, गुंडा, कर्फ्यू, अराजकता, दंगा से मुक्त है. यहां हर व्यक्ति, निवेशक को सुरक्षा की गारंटी है. हम निवेशक को केवल निवेशक नहीं मानते, बल्कि वह इन्वेस्टर पार्टनर के रूप में यूपी सरकार के साथ विकास में सहभागी बनकर कार्य करता है. यूपी में निवेश करने वाला निवेशक प्रदेश के विकास में सरकार का सहयात्री है. वह यूपी के नौजवानों को रोजगार देता है, उन्हें स्किलफुल बनाता है. सरकार हर निवेशक का यूपी में स्वागत करती है.

सीएम योगी ने कहा कि यूपी के पास 34 सेक्टोरल पॉलिसी हैं. एफडीआई की डेडिकेटेड पॉलिसी, फॉर्चून 500 की पॉलिसी है। 25 हजार हेक्टेयर का बड़ा लैंडबैंक यीडा के पास विकसित करने जा रहे हैं. बीडा नए इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में विकसित हो रहा है. इसमें कानपुर व झांसी के बीच 56 हजार एकड़ लैंड उपलब्ध होगी.

सीएम ने बताया कि गत वर्ष 156 करोड़ पर्यटक यूपी में आए. यूपी कभी बीमारू नहीं था. राजनीतिक नेतृत्व की मानसिकता ने इसे बीमार बनाया था. यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला राज्य था. गुंडों के पीछे दुम दबाकर चलने की प्रवृत्ति और माफिया के सामने नतमस्तक होने वाले राजनीतिक नेतृत्व ने यूपी को बीमारू बनाया था, जब स्वस्थ मानसिकता के साथ डबल इंजन सरकार आई तो यूपी आज देश का इकॉनमी का ब्रेकथ्रू बन चुका है.

ट्विशा शर्मा के बाद सपना चौधरी को लेकर आई बड़ी खबर, शादी के 5 साल बाद ये क्या हुआ?

(जीएनएस)।

भोपाल में रह रहीं मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत ने जहां एक तरफ पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, वहीं अब हरियाणवी इंडस्ट्री की मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी और उनकी शादीशुदा लाइफ को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सपना चौधरी एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं।

क्या हुआ सपना चौधरी की शादीशुदा जिंदगी में?

सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से सपना चौधरी और उनके पति वीर साहू (शी१ रँ४) के रिश्ते को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। अब खुद सपना चौधरी ने अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है।

रिश्ता निभा रही हूं पर प्यार महसूस नहीं होता

-हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सपना चौधरी ने अपनी निजी जिंदगी के कई पहलुओं पर खुलकर बात की है। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वह एक पत्नी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभा रही हैं लेकिन रिश्ते में अब पहले जैसा एहसास नहीं बचा है।

-सपना चौधरी ने कहा कि प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं होता बल्कि वह एक ऐसा एहसास है जो इंसान की आत्मा को छू जाए। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चचाएं शुरू हो गई हैं। फैंस ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर सपना अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर इतना भावुक क्यों नजर आ रही हैं।

क्या पति वीर साहू से हुई सपना चौधरी की लड़ाई?

-इंटरव्यू के दौरान सपना चौधरी से ये भी पूछा गया कि पति-पत्नी के बीच जब मनमुटाव होता है तो पहले कौन मनाता है। इस सवाल पर सपना चौधरी ने बेहद बेबाक अंदाज में जवाब दिया।

-सपना चौधरी ने कहा कि उनके और वीर साहू के बीच लड़ाई जैसी स्थिति कम ही बनती है क्योंकि दोनों अपनी-अपनी राय खुलकर रखते हैं। सपना ने बताया कि वह अपनी बात कहकर आगे बढ़ जाती हैं और बेवजह बहस में समय बर्बाद करना पसंद नहीं करतीं।

'मेरे रिश्ते में बहुत कुछ 'धुंधला-धुंधला' दिख रहा है'

सपना चौधरी ने ये भी कहा कि हर रिश्ते में अलग-अलग सोच होना स्वाभाविक है लेकिन अब उन्हें रिश्तों में बहुत कुछ 'धुंधला-धुंधला' महसूस होने लगा है। उनकी ये बात फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे उनके रिश्ते की मौजूदा स्थिति से जोड़कर देख रहे हैं।

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com•navsarjansanskruti2016@yahoo.com•Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

पीएम की यात्रा से भारत-इटली संबंध 'स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' स्तर पर हुए ऊंचे

पीएम मोदी की रोम की यह यात्रा दशार्ती है कि जब नेतृत्व सशत्त हो, दृष्टि स्पष्ट हो और राष्ट्रीय हित सवरेपरि हों, तब परिणाम इतिहास की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। यह वह समय है जब दुनिया नए समीकरण गढ़ रही है और भारत उसमें दर्शक नहीं, सव्रिय निमार्ता की भूमिका निभा रहा है।

मेलोनी को टॉफी, विपक्ष को तमाचा-मोदी ने रोम में नया इतिहास रचा रोम की ऐतिहासिक प्राचीरों के साए में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉंजिया मेलोनी को 'मेलोडी' टॉफी का पैकेट भेंट किया, तो दुनिया ने सिर्प एक मीठा पल नहीं, बल्कि वैश्विक विश्व व्यवस्था में भारत की बढ़ती ताकत और प्रभाव का स्पष्ट संकेत देखा। यह 'मेलोडी' डिप्लोमेसी महज वायरल सेल्फी या कोलोसियम की सैर नहीं थी। यह दो मजबूत राष्ट्रवादियों के बीच उस रणनीतिक गठबंधन की शुरूआत थी,जो यूरोप के मध्य में भारत को नया द्वार खोल रहा है। जबकि विपक्ष 'टॉफी डिप्लोमेसी' पर तंज कस रहा है, हकीकत यह है कि मोदी की इस यात्रा ने भारत-इटली संबंधों को 'स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' स्तर पर ऊंचा उठा दिया है। पुरानी कांग्रेस संस्वृति की 'चाय पी लो' वाली आलोचना अब पुरानी पड़ चुकी है। वैश्विक वूटनीति के बदलते परिदृश्य के बीच इस दौरे में दोनों देशों ने संयुत्त 'जॉइंट स्ट्रैटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029' की समीक्षा की और कई ठोस आउटकम्स/एम.ओ.यूज़ पर सहमति जताई। द्विपक्षीय व्यापार को 2029 तक 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया। रक्षा उद्योग सहयोग, व्रिटिकल मिनरल्स, समुद्री परिवहन, वृषि, उच्च शिक्षा, नर्स भता और आयुव्रेद जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक समझौते हुए। सबसे महत्वपूर्ण, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) को नई गति मिली। इटली भूमध्य सागर का अहम प्रवेश द्वार है, जिससे यह साझेदारी भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति को 'एक्ट वेस्ट' की दिशा में भी मजबूत आधार देती है। जबकि विपक्ष 'मेलोडी' पर व्यंग्य कर रहा है, वास्तविकता यह है कि मोदीमेलोनी ने दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की ठोस नींव रखी है। यह यात्रा महज द्विपक्षीय नहीं,बल्कि बहुपक्षीय महत्व की है। दोनों नेताओं ने वैश्विक मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। चीन के बढ़ते आामक रवैये,ऊर्जा सुरक्षा और आपरूति श्रृंखला की विविधता पर सहमति बनी। दोनों देशों ने एक्शन प्लान की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों के नेतृत्व वाले एक मैकेनिज़्म के गठन पर सहमति जताई है। यह संस्थागत मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेलोनी की सरकार मजबूत राष्ट्रवादी रुख के साथ अवैध प्रवासन और यूरोपीय संप्रभुता पर सख्त नीति अपनाती है,जबकि मोदी की 'आत्मनिर्भर भारत' और मेलोनी की 'इटली फर्स्ट' सोच में स्पष्ट समानता दिखती है। दोनों ने साफ संदेश दिया कि लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की नींव पर खड़े देश एक-दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं, वैश्विक संतुलन को नई दिशा दे सकते हैं। यह वह सोच है जिससे कांग्रेस और उसके गठबंधन वाले हमेशा कतराते रहे। वे तो अभी भी'चीन भाई-चीन'वाली पुरानी लीक पर अटके हैं। इतिहास के पन्नों में यह यात्रा केवल राजनीतिक नहीं,बल्कि सांस्वृतिक जुड़ाव की एक सशत्त मिसाल के रूप में दर्ज हुई। कोलोसियम में संयुत्त भ्रमण, राजकीय रात्रिभोज, गार्ड ऑफ ऑनर और मेलोनी द्वारा हिदी कहावत 'परिश्रम ही सफलता की वुंजी है' का उल्लेख-ये सभी क्षण दोनों देशों के बीच बढ़ती आत्मीयता को दशार्ते हैं। इटली में भारतीय समुदाय की उपस्थिति और सव्रियता लगातार मजबूत हो रही है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। भले ही वुछ लोग सांस्वृतिक वूटनीति को कम आँकते हों,पर वास्तविकता यह है कि सॉफ्ट पावर के बिना वैश्विक प्रभाव अधूरा रहता है,और इसी संतुलन को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। भारत और यूरोप के बीच आर्थिक रिश्ते अब नए विस्तार की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 16.77 बिलियन डॉलर के व्यापार आधार के साथ यह साझेदारी निवेश,तकनीक और संयुत्त उत्पादन को नई ऊर्जा दे रही है। रक्षा क्षेत्र में सह-उत्पादन के अवसर मजबूत हो रहे हैं,वहीं स्वच्छ ऊर्जा और एआई जैसे भविष्य-वेंद्रित क्षेत्रों में सहयोग भारत को यूरोपीय तकनीकी क्षमता से और अधिक जोड़ रहा है। वैश्विक आपरूति श्रृंखला को चीन से अलग करने की चल रही कोशिशों के बीच भारत की रणनीतिक भूमिका लगातार बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदशा नीति ने इस परिवर्तन में भारत को निर्णायक स्थिति में ला खड़ा किया है,जबकि विपक्ष अब भी बड़े आर्थिक दृष्टिकोण की बजाय सीमित मुद्दों तक ही सिमटा दिखाई देता है। विपक्ष की आलोचना इस दौर की एक चिताजनक सच्चाई बनकर सामने आती है। राहुल गांधी जैसे नेता जब 'टॉफी डिप्लोमेसी' पर व्यंग्य करते हैं,तो वे देश की गरिमा और विदेश नीति की गंभीरता को कमजोर करते प्रतीत होते हैं। जब भारत वैश्विक पटल पर मजबूती से अपनी स्थिति स्थापित कर रहा है,तब भी उन्हें विदेश नीति केवल 'मोदी का प्रचार' कहकर सीमित करने की प्रवृत्ति से आगे बढ़ते नहीं देखा जाता। यह भी स्मरणीय है कि वही विपक्ष पहले 'चीन के साथ दोस्ती' जैसे विचारों को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करता रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी इटली जैसे मजबूत यूरोपीय देश के साथ रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा दे रहे हैं,तब उनकी चुप्पी या तीखी आलोचना दोनों ही व्यापक राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में प्रश्न उठाती है। मोदी-मेलोनी की यह 'मेलोडी', डिप्लोमेसी अब केवल एक वूटनीतिक संवाद नहीं,बल्कि बदलती वैश्विक शत्ति संरचना में भारत के निर्णायक उभार का स्पष्ट संकेत बन चुकी है। रोम की यह यात्रा दशार्ती है कि जब नेतृत्व सशत्त हो, दृष्टि स्पष्ट हो और राष्ट्रीय हित सवरेपरि हों,तब परिणाम इतिहास की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। यह वह समय है जब दुनिया नए समीकरण गढ़ रही है और भारत उसमें दर्शक नहीं, सव्रिय निमार्ता की भूमिका निभा रहा है।

₹143579 करोड़ की 5th जेन फाइटर जेट डील, पाकिस्तान ने बढ़ाई भारत की टेंशन, राफेल से कितना ताकतवर यह एयरक्राफ्ट

दुनियाभर में सामरिक हालात लगातार बदल रहे हैं. बदलते माहौल के तहत तमाम देश अपने डिफेंस सिस्ट टम को लगातार एडवांस और अपग्रेड करने में जुटा है. भारत भी इसका अपवाद नहीं है. स्वदेशी स्तर पर नेक्स्ट जेनरेशन का फाइटर जेट डेवलप करने को लेकर खास प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है. इसके सथ ही सवा तीन लाख करोड़ रुपये में फ्रांस से 114 राफेल F4 जेट खरीदने का करार भी किया गया है. दूसरी तरफ, पाकिस्तान भी अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने में जुटा है. इसके तहत बड़ा कदम उठाया गया है.

पाकिस्तान ने तुर्की के साथ पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट को लेकर अरबों डॉलर का सौदा किया है. हालांकि, दोनों देशों की ओर से इस करार की पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है.

भारत पूरी प्लानिंग के तहत अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है. फाइटर जेट से लेकर मिसाइल, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम तक डेवलप किए जा रहे हैं. फ्रांस से 114 राफेल जेट खरीदने का सौदा किया गया है. इसे देश के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील बताया जा रहा है. वहीं, नेक्स्ट जेनरेशन का फाइटर जेट बनाने के लिए स्वेदशी स्तर पर AMCA प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है. इसका उद्देश्य पांचवीं पीढ़ी और उससे आगे का लड़ाकू विमान डेवलप करना है. चीन पहले ही 5th जेनरेशन का स्टील्थ जेट बना चुका है. अब पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि पाकस्तिान ने तुर्की के साथ बड़ी डिफेंस डील की है, जिसके तहत इस्ट लामाबाद पांचवीं पीढ़ी का 65 फाइटर जेट खरीदेगा. हालांकि, अभी तक दोनों देशों की तरफ से इस महाडील की पुष्टि नहीं की गई है. ऐसा होने पर दक्षिण एशिया में पावर बैलेंस गड़बड़ा सकता है. यदि मीडिया रिपोर्ट सही है तो पाकस्तिान का यह कदम चीन के प्रति उसके मोहभंग को भी दिखाता है. इससे पहले इस बात की चर्चा थी कि पाकिस्तान अपने परंपरागत सहयोगी चीन से पांचवीं पीढ़ी का फाइटर जेट खरीदेगा, लेकिन अब इस्लामाबाद ने अंकारा का रुख कर लिया है

तुर्की और पाकिस्तान के बीच कथित तौर पर 65 अत्याधुनिक ङअअठ फिफ्थ जेनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट्स की खरीद को लेकर 15 अरब डॉलर (₹143579 करोड़ भारतीय मुद्रा में, पाकिस्तान मुद्रा में 417741 करोड़ रुपया) की बड़ी डिफेंस डील की खबर ने वैश्विक रक्षा जगत में हलचल पैदा कर दी है. 'इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग' की रिपोर्ट के अनुसार, तुर्की के एक डफिंस जर्नलिस्ट ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच यह समझौता हो चुका है, हालांकि अभी तक न तो पाकिस्तान सरकार और न ही तुर्की की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है. यदि यह समझौता सही साबित होता है, तो यह पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी रक्षा खरीद में से एक माना जाएगा. साथ ही यह तुर्की के स्वदेशी फिफ्थ जेनरेशन लड़ाकू विमान कार्यक्रम KAAN के लिए भी बड़ा निर्यात अवसर साबित हो सकता है. KAAN (जिसे पहले TF- या MMU नाम से जाना जाता था) तुर्की का स्वदेशी स्टील्थ फाइटर जेट है. इसे अत्याधुनिक एवियोनिक्स, कम रडार पहचान क्षमता और एयर सुपीरियोरिटी मिशनों के लिए विकसित किया गया है.

तुर्की का पहला स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट TAI KAAN तेजी से अंतरराष्ट्रीय रक्षा बाजार में अपनी पहचान बना रहा है. इसे Turkish Aerospace Industries (TAI) ने विकसित किया है और इसने फरवरी 2024 में अपनी पहली सफल उड़ान भरी थी. फ्रांस द्वारा विकसित डसॉल्ट राफेल F4 एक अत्याधुनिक 4.5वीं पीढ़ी का मल्टीरोल फाइटर जेट है, जिसे एयर सुपीरियरिटी, न्यूक्लियर डिटरेंस और डीप-स्ट्राइक मिशनों के लिए तैयार किया गया है. यह राफेल के सबसे आधुनिक संस्करणों में गिना जाता है.

KAAN एक ट्विन-इंजन, ऑल-वेदर और एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर विमान है, जिसे कम रडार पहचान (Low Radar Cross Section) और स्टेल्थ क्षमता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. विमान में इंटरनल वेपन बे दिए गए हैं, जिससे इसकी रडार विजिबिलिटी और कम हो जाती है.
राफेल F4 की सबसे बड़ी खासियत इसकी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता है. यह फाइटर जेट सैटेलाइट, ग्राउंड कमांड नेटवर्क और अन्य लड़ाकू प्लेटफॉर्म्स के साथ रियल टाइम डेटा साझा कर सकता है, जिससे युद्धक्षेत्र में तेज और सटीक फैसले लेने में मदद मिलती है.

विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी सुपरक्रूज क्षमता मानी जा रही है. ट्विन-इंजन कॉन्फिगरेशन के कारण यह बिना आफ्टरबर्नर के लंबे समय तक सुपरसोनिक गति बनाए रखने में सक्षम होगा. इस विमान में अपग्रेडेड RBE2 AESA रडार, एडवांस SPECTRA इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और थेल्स स्कॉर्पियन हेलमेट-माउंटेड डिस्प्ले जैसे आधुनिक सेंसर लगाए गए हैं. इससे पायलट को दुश्मन के लक्ष्यों की तेजी से पहचान और ट्रैकिंग में मदद मिलती है.

KAAN में तुर्की की स्वदेशी एवियोनिक्स और सेंसर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इसमें Aselsan द्वारा विकसित Karat Infrared Search and Track (IRST) सिस्टम और Toygun इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम लगाया गया है. इसके अलावा KEMENT Tactical Data Link के जरिए यह रियल टाइम नेटवर्किंग और ड्रोन के साथ संयुक्त ऑपरेशन करने में सक्षम होगा. हथियार क्षमता के मामले में राफेल F4 लंबी दूरी की

Meteor BVR मिसाइल और 1,000 किलोग्राम तक के अरट1000 प्रिसिजन गाइडेड बम ले जाने में सक्षम है. इसके अलावा इसमें अकसहायता प्राप्त टार्गेटिंग सिस्टम और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस तकनीक भी शामिल की गई है.

Turkish Aerospace Industries के अनुसार, KAAN की शुरूआती डिलीवरी 2028 के अंत तक तुर्की वायुसेना को शुरू करने का लक्ष्य है, जबकि इसकी पूर्ण ऑपरेशनल क्षमता 2030 के शुरूआती वर्षों तक हासिल होने की उम्मीद है. इस बीच इंडोनेशिया समेत कई देशों ने इसमें रुचि दिखाई है और पाकिस्तान व सऊदी अरब के साथ भी रक्षा सहयोग बढ़ने की चर्चा है. फ्रांस की वायुसेना और नौसेना में राफेल F4.1 मुख्य ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म बन चुका है. वहीं भारत ने 114 राफेल विमानों की खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है. भारतीय संस्करण को F4+ कहा जा रहा है, जिसमें स्वदेशी हथियार, सुरक्षित डेटा लिंक और स्टील्थ विमान पहचानने में सक्षम उन्नत रडार शामिल होंगे. इन विमानों का बड़ा हिस्सा नागपुर में असेंबल किए जाने की योजना है.

लंबे समय से पक रही थी खिचड़ी

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान लंबे समय से KAAN कार्यक्रम में रुचि दिखाता रहा है. दोनों देशों के बीच पहले भी खङ्क-17 लड़ाकू विमान जैसे कई रक्षा सहयोग कार्यक्रम चल चुके हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तानी इंजीनियर भी ङअअठ प्रोजेक्ट के विकास में शामिल रहे हैं और ज्वाइंट प्रोडक्शन फैशिलिटी स्थापित करने पर भी चर्चा हो चुकी है. ऐसे में यह डील केवल विमान खरीद तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्थानीय उत्पादन जैसे बड़े औद्योगिक सहयोग का रास्ता भी खोल सकती है. पाकिस्तान के लिए यह सौदा उसकी वायु शक्ति में बड़ा रणनीतिक बदलाव ला सकता है. यदि उसे बड़ी संख्या में फिफ्थ जेनरेशन स्टील्थ विमान मिलते हैं, तो उसकी वायुसेना की क्षमताओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी. माना जा रहा है कि ये विमान पाकिस्तान के मौजूदा लड़ाकू बेड़े के साथ मिलकर क्षेत्रीय संतुलन और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं.

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो हजारों करोड़ की इस डील के तहत पाकिस्तान मित्र देश तुर्की से 65 स्टील्थ एयरक्राफ्ट खरीदेगा.

दूसरी ओर, तुर्की के लिए यह डील उसके रक्षा निर्यात कार्यक्रम की बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है. राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन के नेतृत्व में तुर्की पिछले कुछ वर्षों से अपनी घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत करने पर जोर दे रहा है, ताकि विदेशी हथियार पर निर्भरता कम की जा सके. ङअअठ प्रोजेक्ट ट इसी रणनीति का प्रमुख हिस्सा मानी जाती है. तुर्की पहले ही अपने वायुसेना कार्यक्रम के लिए ङअअठ के शुरूआती करार कर चुका है और अब मित्र देशों को इसका निर्यात बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इंडोनेशिया और अजरबैजान जैसे देशों के साथ भी ङअअठ को लेकर बातचीत चल रही है. ऐसे में पाकिस्तान के साथ संभावित समझौता तुर्की को फिफ्थ जेनरेशन लड़ाकू विमान बाजार में एक नए खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकता है.

तुर्की-पाकिस्तान के बीच किस डिफेंस डील का दावा किया गया है?

एक तुर्की रक्षा पत्रकार ने दावा किया है कि तुर्की और पाकिस्तान के बीच 65 ङअअठ फिफ्थ-जेनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट्स की खरीद के लिए करीब 15 अरब डॉलर की बड़ी रक्षा डील हुई है. अगर यह समझौता सही साबित होता है, तो यह पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी रक्षा खरीद में शामिल होगा.

KAAN फाइटर जेट की खासियत क्या है?

ङअअठ तुर्की का स्वदेशी फिफ्थ-जेनरेशन स्टील्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे पहले TF- या MMU नाम से भी जाना जाता था. इसमें लो-ऑब्जर्वेबल स्टील्थ डिजाइन, आधुनिक एवियोनिक्स, एयर सुपीरियॉरिटी क्षमता और एडवांस हथियार प्रणाली जैसी खूबियां शामिल हैं.

क्या इस डील की आधिकारिक पुष्टि हुई है?

फिलहाल पाकिस्तान सरकार, क्रढफ तुर्की के रक्षा मंत्रालय या से इस डील की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. इसलिए इस खबर को लेकर अभी सतर्कता बरती जा रही है.

पाकिस्तान को इस डील से क्या रणनीतिक फायदा हो सकता है?

अगर पाकिस्तान को ङअअठ जेट्स मिलते हैं, तो उसकी वायुसेना की ताकत में बड़ा इजाफा होगा. इससे पाकिस्तान की स्टील्थ और एयर कॉम्बैट क्षमता मजबूत होगी, साथ ही क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर भी असर पड़ सकता है.

तुर्की और पाकिस्तान के रक्षा सहयोग का महत्व क्या है?

दोनों देशों के बीच पहले से खङ्क-17 जैसे प्रोजेक्ट्स में सहयोग रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के इंजीनियर ङअअठ प्रोग्राम में भी योगदान दे रहे हैं. संभावित डील से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, संयुक्त उत्पादन और दीर्घकालिक रक्षा औद्योगिक साझेदारी को बढ़ावा मिल सकता है.

अभी तक डिफेंस डील की पुष्टि नहीं

हालांकि, फिलहाल इस पूरे मामले में आधिकारिक पुष्टि का अभाव बना

लगातार सस्ती हो रही चांदी, आज भी गिरे दाम? कितना है एक किलो सिल्वर का रेट

(जीएनएस)।

महंगाई और बाजार में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव के बीच अब लोग निवेश के लिए सिर्फ सोने पर ही निर्भर नहीं रह रहे हैं। चांदी भी धीरे-धीरे लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है, क्योंकि कम बजट में इसमें निवेश करना आसान माना जाता है। यही वजह है कि छोटे निवेशक से लेकर आम परिवार तक चांदी की खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

शादी-ब्याह, त्योहार और गिफ्टिंग में भी चांदी की मांग हमेशा बनी रहती है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में चांदी के दाम में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए लोग इसके ताजा रेट पर नजर बनाए हुए हैं। आज चांदी की कीमत ₹285 प्रति ग्राम और ₹2,85,000 प्रति किलो दर्ज की गई है।

आज चांदी के ताजा भाव

आज भारत में चांदी की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। ज्यादातर शहरों में रेट स्थिर बने हुए हैं।

1 ग्राम चांदी - ₹285
8 ग्राम चांदी - ₹2,280
10 ग्राम चांदी - ₹2,850
100 ग्राम चांदी - ₹28,500
1 किलो चांदी - ₹2,85,000

पिछले 10 दिनों में कैसे बदले दाम

पिछले कुछ दिनों में चांदी के दाम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। कभी तेजी तो कभी गिरावट के कारण निवेशकों की नजर लगातार बाजार पर बनी हुई है।

22 मई 2026 - ₹2,85,000 प्रति किलो
21 मई 2026 - ₹2,85,000 प्रति किलो
20 मई 2026 - ₹2,80,000 प्रति किलो
19 मई 2026 - ₹2,85,000 प्रति किलो
18 मई 2026 - ₹2,90,000 प्रति किलो
17 मई 2026 - ₹2,80,000 प्रति किलो
16 मई 2026 - ₹2,80,000 प्रति किलो
15 मई 2026 - ₹2,90,000 प्रति किलो
14 मई 2026 - ₹3,00,000 प्रति किलो
13 मई 2026 - ₹3,10,000 प्रति किलो

बड़े शहरों में चांदी का भाव

देश के कई बड़े शहरों में आज चांदी के रेट लगभग समान बने हुए हैं।

दिल्ली - ₹2,85,000 प्रति किलो
मुंबई - ₹2,85,000 प्रति किलो
जयपुर - ₹2,85,000 प्रति किलो
लखनऊ - ₹2,85,000 प्रति किलो
पुणे - ₹2,85,000 प्रति किलो
अहमदाबाद - ₹2,85,000 प्रति किलो
पटना - ₹2,85,100 प्रति किलो

MCX पर चांदी का भाव

मल्टी कमोडिटी बाजार में शुक्रवार सुबह चांदी के वायदा भाव में हल्की गिरावट देखने को मिली। 03 जुलाई 2026 एक्सपायरी वाली चांदी ₹274662 प्रति किलो पर कारोबार करती नजर आई, जिसमें ₹221 यानी करीब 0.08 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। आज के कारोबार के दौरान चांदी का न्यूनतम भाव ₹273266 और उच्चतम भाव ₹275000 तक पहुंचा।

वहीं इसका पिछला बंद भाव ₹274883 रहा। बाजार आंकड़ों के अनुसार, चांदी का औसत भाव ₹274331.83 प्रति यूनिट दर्ज किया गया। इस दौरान कुल 464 लॉट का कारोबार हुआ, जबकि ओपन इंटरेस्ट 9219 लॉट रहा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैश्विक बाजार और निवेशकों की खरीदारी के असर से आने वाले दिनों में चांदी के दाम में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

आ गया एलपीजी का स्वदेशी विकल्प! देश का पहला डाइमिथाइल ईथर प्लांट में उत्पादन शुरू, रसोई गैस की टेंशन होगी खत्म

(जीएनएस)।

भारत ने महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में बालाजी एमाइंस लिमिटेड द्वारा देश का पहला वाणिज्यिक स्तर का डाइमिथाइल ईथर (उ्टए) मैन्युफैक्चरिंग प्लांट (विनिर्माण संयंत्र) चालू करके, दूसरे ईंधन को अपनाने और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है.

कंपनी ने 20 मई से चिंचोली महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) में अपनी 100,000 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) DME प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. यह प्रोजेक्ट वैश्विक भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं और अस्थिर ऊर्जा बाजार के बीच आयातित एलपीजी पर निर्भरता कम करने की भारत की कोशिशों में एक संभावित गेम चेंजर के तौर पर सामने आया है.

क्ल्ल्रि ॗ१२३ ोि ॗ्रं'३८ ॗ्ल्लर२ स्र१ङ्क्ष्र्३ङ्कल्ल रीर२ र्ङ्कस्री ३ङ्क् ४३ छढक्क्सङ्क१३२ ल्ल्रिू ल्लिी१ ।ठी' श्ँ३

डाइमिथाइल ईथर (DME) मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सोलापुर (ETV ईँ१३)

डाइमिथाइल ईथर को एक क्लीन-बर्निंग फ्यूल माना जाता है जो या तो LPG को पूरी तरह से हटा सकता है या उसके साथ ब्लेंड किया जा सकता है. यूरोप और एशिया के कई देश पहले से ही LPG के साथ 20 प्रतिशत तक के अनुपात में उ्टए को ब्लेंड करते हैं. भारत में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने हाल ही में एलपीजी के साथ 8 प्रतिशत तक डाइमिथाइल ईथर को ब्लेंड करने की इजाजत दी है, जिससे घरेलू ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र में इसे धीरे-धीरे अपनाने का रास्ता खुल गया है.

यह विकास ऐसे समय में हुआ है जब भारत अपनी LPG जरूरतों का लगभग एक-चौथाई हिस्सा आयात करता है, जिससे देश को ग्लोबल सप्लाई में रुकावटों और मिडिल ईस्ट और दूसरे ऊर्जा बनाने वाले इलाकों में तनाव से जुड़ी कीमतों में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, अनुभवी वैज्ञानिक और नीति आयोग के पूर्व सदस्य वी के सारस्वत ने कहा, "डाइमिथाइल ईथर (DME) एक जरूरी वैकल्पिक ईंधन के तौर पर उभर रहा है. यह या तो एलपीजी का स्थान ले सकता है या फिर इसके साथ मिलाकर इम्पोर्टेड छढक्क पर भारत की भारी निर्भरता को कम कर सकता है."

उन्होंने बताया कि, इसका मकसद लंबे समय के लिए देसी तकनीक और स्थानीय फीडस्टॉक संसाधन का इस्तेमाल करके उ्टए को देश में ही बनाना है. उनके मुताबिक, डाइमिथाइल ईथर उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला मुख्य कच्चा माल मेथनॉल, कोयला आधारित प्रक्रिया सहित कई तरीकों से बनाया जा सकता है.

सारस्वत ने बताया कि देसी डाइमिथाइल ईथर टेक्नोलॉजी को नेशनल केमिकल लेबोरेटरी (NCL), पुणे ने कैटलिस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पहले ही डेवलप कर लिया है. उन्होंने कहा, "जबकि एक पायलट प्लांट पहले से ही चालू है, कुछ प्राइवेट कंपनियों ने भी इम्पोर्टेड मेथनॉल का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया है."

अगर बालाजी एमाइंस प्लांट को पूरी कैपेसिटी से चलाया जाए, तो यह हर साल करीब 100,000 टन मेथनॉल की खपत करेगा. इंडस्ट्री के आकलन से पता चलता है कि मार्केट में चल रही अनिश्चितताओं की वजह से दुनिया भर में मेथनॉल की कीमतें

लगातार बदल रही हैं. बालाजी एमाइंस के मैनेजिंग डायरेक्टर राम रेड्डी ने इस प्रोजेक्ट को भारत के एनर्जी सिक्योरिटी लक्ष्यों के लिए एक रणनीतिक मील का पत्थर बताया.

रेड्डी ने ईटीवी भारत को बताया, "यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है. अभी, भारत विदेशों से बड़ी मात्रा में छढक्क आयात करता है, और दुनिया भर में चल रही भू-राजनीतिक मुश्किलों की वजह से, हमने देखा है कि वैश्विक हालात भारत की एनर्जी सप्लाई चेन पर सीधे असर डाल सकते हैं. यह देश के लिए एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का सही समय है."

कंपनी का मानना है कि डाइमिथाइल ईथर में होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, बिस्किट बनाने, एयरोसोल एप्लीकेशन, सिरेमिक, बल्ब बनाने और दूसरी इंडस्ट्रीज जैसे सेक्टर में बड़ा कमर्शियल पोटेंशियल है, जो बल्क LPG खपत पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं. रेड्डी ने कहा, "क्योंकि डाइमिथाइल ईथर को एलपीजी के साथ ब्लेंड किया जा सकता है और मौजूदा आधारभूत संरचना के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए यह आने वाले सालों में भारत के लिए एक सस्ता और व्यावहारिक वैकल्पिक ईंधन बन सकता है."

हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि एलपीजी और DME के बीच सीधे मूल्य तुलना अभी मुश्किल है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी संकट और ग्लोबल मार्केट में बड़े पैमाने पर अस्थिरता के कारण कच्चा माल के दाम में तेजी से उतार-चढ़ाव हो रहा है.

डाइमिथाइल ईथर को लेकर जोश के बावजूद, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की घरेलू मेथनॉल उत्पादन क्षमता सीमित है. सारस्वत ने कहा कि कई भारतीय मेथनॉल उत्पादक अभी नेचुरल गैस सप्लाई पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, जिससे आयात निर्भरता की एक और लेयर बन जाती है.

सारस्वत ने कहा, "भविष्य में इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए, भारत को मेथनॉल प्रोडक्शन के लिए कोयला गैसीकरण पर ध्यान देना चाहिए." उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार ने पहले ही 37,500 करोड़ रुपये का कोल गैसीफिकेशन मिशन शुरू कर दिया है, जिसका मकसद इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना और घरेलू उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाना है. एक्सपट्र्स के अनुसार, डाइमिथाइल ईथर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह भारत के मौजूदा छढक्क डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ अनुकूल है. सारस्वत ने बताया कि स्टोरेज सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सिलेंडर और बर्नर काफी हद तक डाइमिथाइल ईथर के साथ अनुकूल हैं, जिनमें सिर्फ मामूली बदलाव की जरूरत है. उन्होंने कहा, "DME के LPG से सस्ता होने की उम्मीद है, जिससे घरों, होटलों, रेस्टोरेंट और छोटे उद्योग को फायदा होगा." भारत अभी 8 प्रतिशत ब्लेंडिंग मॉडल के साथ सावधानी से शुरूआत कर रहा है. सारस्वत ने कहा कि पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनियां अभी भी प्लानिंग फेज में हैं और किसी भी देशव्यापी लागू करने से पहले पायलट प्रोजेक्ट्स का मूल्यांकन किया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'भारत ने 8 फीसदी ब्लेंडिंग मॉडल के साथ शुरूआत की है और टेस्टिंग और वैलिडेशन स्टडीज पूरी होने के बाद भविष्य में इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 20 फीसदी करने का लक्ष्य है.' रेड्डी ने भी इसी तरह के फेज्ड तरीके को दोहराया, और कहा कि 8 फीसदी से 12 फीसदी ब्लेंडिंग से शुरू करने से इंडस्ट्री को मौजूदा LPG इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव किए बिना डाइमिथाइल ईथर अपनाने में मदद मिलेगी.

उन्होंने कहा, "इसके बाद, ब्लेंडिंग अनुपात को धीरे-धीरे चरणबद्ध तरीके से 20 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है. इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, ऑपरेशनल अडैप्टेशन और पूरे सेक्टर में इसे आसानी से लागू करने के लिए काफी समय मिलेगा.' कंपनी ने यह भी बताया कि वह डाइमिथाइल ईथर ब्लेंडिंग और अपनाने की रणनीति के बारे में मंत्रालयों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है.

हालांकि, इस नए सेक्टर के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल एक बड़ी रुकावट बनी हुई है. रेड्डी के मुताबिक, बालाजी एमाइंस को रोड टैंकर, स्टोरेज सिस्टम और सिलेंडर के लिए पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) से परमिशन लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि कमर्शियल लेवल पर उ्टए प्रोडक्शन भारत में नया है.

यूपी में होगी मौसम की सटीक भविष्यवाणी; सीएम योगी का निर्देश- 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' भी हो मजबूत

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में मौसम संबंधी पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक सटीक, त्वरित तथा जनकेंद्रित बनाने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को राहत एवं आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समय पर दी गई सही सूचना अनेक लोगों का जीवन बचा सकती है। इसलिए मौसम पूवार्नुमान और चेतावनी तंत्र को केवल तकनीकी व्यवस्था तक सीमित न रखते हुए अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने गांवों और संवेदनशील क्षेत्रों में 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' मजबूत करने, आईवीआरएस, पंचायत स्तर के लाउडस्पीकर, स्थानीय एफएम रेडियो, मोबाइल अलर्ट तथा सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग करने के निर्देश दिए।

बैठक में 13 मई 2026 को आए भीषण आंधी-तूफान की समीक्षा प्रस्तुत की गई। बताया गया कि आईएमडी के मल्टी-हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम (एमएचईडब्ल्यूएस) द्वारा इस घटना की सात दिन पहले से निगरानी की जा रही थी। प्रारंभ में येलो वार्निंग जारी की गई, जिसे बाद में ऑरेंज वार्निंग तथा कई जिलों में रेड अलर्ट में अपग्रेड किया गया। चेतावनियों में तेज आंधी, बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रफ्तार वाली हवाओं की आशंका जताई गई थी। कई स्थानों पर हवा की गति 80 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई।

बैठक में बताया गया कि भदोही, प्रयागराज, फतेहपुर, लखनऊ, मिजार्पुर, रायबरेली, कानपुर नगर और उन्नाव सहित अनेक जिलों के लिए

70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवा चलने संबंधी नाउकास्ट अलर्ट जारी किए गए थे। 'सचेत' प्लेटफॉर्म के माध्यम से कलर-कोडेड अलर्ट जिला प्रशासन, डीडीएमए, आपदा मित्रों और संबंधित विभागों तक पहुंचाए गए। प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय मोबाइल फोनों पर एसएमएस आधारित चेतावनियां भी भेजी गईं। पूरी घटना के दौरान लगातार एसएमएस अलर्ट जारी किए गए। स्थानीय टीवी चैनलों, एफएम रेडियो, व्हाट्सएप समूहों, ग्राम प्रधानों, लेखपालों तथा आशा और आंगनबाड़ी कार्यकताओं के माध्यम से भी व्यापक स्तर पर सूचना प्रसारित की गई। मुख्यमंत्री ने मौसम संबंधी पूर्व सूचना मिलने के बाद संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चेतावनी जारी करने के साथ-साथ लोगों में सुरक्षित व्यवहार को लेकर जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है। उन्होंने स्कूलों, पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही पेड़ों, बिजली के खंभों, होर्डिंग्स और कमजोर अस्थायी संरचनाओं की संवेदनशीलता का स्थानीय स्तर पर आकलन कर एसओपी तैयार करने को कहा।

बैठक में बताया गया कि आईएमडी द्वारा डॉप्लर वेदर रडार, ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (एडब्ल्यूएस), ऑटोमैटिक रेन गेज स्टेशन (एआरजी), लाइटनिंग सेंसर, सैटेलाइट इमेज तथा न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स के माध्यम से प्रदेश में मौसम की लगातार निगरानी की जा रही है। मीडियम रेंज फोरकास्ट (4-5 दिन), शॉर्ट रेंज फोरकास्ट (2-3 दिन) तथा नाउकास्ट (3 घंटे तक) स्तर पर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग गतिविधियों का पूवार्नुमान जारी किया जाता है।

प्रदेश में 450 ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन तथा 2000 ऑटोमैटिक रेन गेज स्थापित किए जा चुके हैं। अलीगढ़, झांसी, लखनऊ, वाराणसी और आजमगढ़ में डॉप्लर वेदर रडार स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि बरेली, देवरिया और प्रयागराज में अतिरिक्त रडार लगाने की प्रक्रिया जारी है। लखनऊ और प्रयागराज में विंड प्रोफाइलर रडार स्थापित किए जाने की कार्यवाही भी प्रगति पर है।

बैठक में बताया गया कि यूएनडीपी के सहयोग से प्रदेश के 15 विभागों, सभी 75 जिलों तथा 20 प्रमुख नगरों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार किए जा रहे हैं। वर्ष 2025 में 44 जिलों की 118 तहसीलों में लगभग 1800 स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया, जिनके माध्यम से 2361 गांवों और 4824 मजरों में जनजागरूकता अभियान चलाया गया। 'आपदा मित्र' स्वयंसेवकों को बीमा प्रमाण-पत्र वितरित किए गए हैं तथा नाव दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए 38 जिलों में 66,077 लाइफ जैकेट वितरित किए गए हैं।

आसमान से बरसी आग तो मध्य प्रदेश के आईपीएस ने यूपी सीएम योगी से की अपील

(जीएनएस)।

भोपाल : दुनिया के सबसे गर्म शहरों में से एक बन चुके यूपी के बांदा को लेकर एमपी के कद्दर अफसर ने चिंता जताई है. हाल ही में स्टेट बायोडायवर्सिटी अवॉर्ड से सम्मानित आईपीएस ने इस कदर चढ़ते तापमान की चिंता में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ऑडियो संदेश भेजा है. मध्यप्रदेश में एडीजी रेलवे, रामबाबू सिंह ने सबसे गर्म शहर की इस पहचान को बांदा पर लगा दाग बताया है, और कहा है कि हम इसे धोकर रहेंगे.

उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वहां अवैध उत्खनन पूरी तरह प्रतिबंधित हो. साथ ही दस साल के लिए माइन व मिनरल का ठेका बंद किया जाए. एडीजी राजाबाबू सिंह ने बताया कि कैसे प्लांटेशन ड्राइव के साथ बांदा की तस्वीर बदली जा सकती है और कैसे धुल सकता है बांदा पर लगा ये दाग.

मध्यप्रदेश के IPS अफसर की योगी से ये अपील

करीब पचास सेकंड के इस ऑडियो संदेश में राजा बाबू सिंह अपना परिचय देते हुए कहा, " मैं राजा बाबू सिंह 1994 बैच का आईपीएस हूं. जो कि एडीजे रेलवे के रूप में मध्यप्रदेश में पदस्थ हूं. मैं बांदा जिले का मूलनिवासी हूं. मैं पिछले कुछ दिनों से पेपरों में पढ़ रहा हूं कि बांदा में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच रहा है. बांदा दुनिया के कुछ गर्म स्थानों में से एक बन गया है, ये मेरे

लिए बहुत ही आत्मिक कष्ट का विषय है." वे आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहते हैं, " मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाराज श्री योगी जी से ये अनुरोध करूंगा. कि वहां जो अवैध उत्खनन हो रहा है. रेत उत्तखनन हो रहा है. पहाड़ियां खत्म की जा रही है. उन पर तत्काल प्रतिबंध लगे."

आईपीएस ने सुझाया तापमान नियंत्रण का तरीका

इस संकट से निपटने का रास्ता सुझाते हुए आईपीएस ने कहा, " बांदा, महोबा, हमीदपुर में अगले दस सालों के लिए माइनर मिनरल का ठेका बंद किया जाए. इसी जुलाई से कमिटमेंट के साथ ईमानदारी से मास प्लांटेशन किया जाए. इन तीन जिलों में 33 प्रतिशत का फॉरेस्ट कवर दुबारा सथापित हो जाए. जैव विविधिता पुर्नस्थापित पुर्नजीवित हो. बांदा पूरी दुनिया में गर्म स्थानों में से एक है. इस दाग को इस तरह से हम धो सकेंगे, जरुर धोंएगे." वे आगे कहते हैं, " मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरी विनम्र प्रार्थना को जरुर सुनेंगे."

'मैं चाहता हूं कि दुनिया के नक्शे में मेरे बांदा पर लगा ये दाग मिटे'

एडीजी रेलवे राजाबाबू सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, " कल ही मुझे स्टेट बायोडायवर्सिटी अवार्ड मिला है. मैं एक पर्यावरणविद भी हूं. मूल निवासी हूं बांदा का. अब तक दुनिया के सबसे गर्म शहर के तौर पर मेरे बांदा की पहचान हो रही है, तो मैंने ये अपील जारी की है. उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम है ये अपील. वहां माइनिंग रोकी जानी चाहिए. केन-बेतवा जो बांदा, महोबा, हमीदपुर की जीवन रेखा हैं, इन्हें पुर्नजीवित करना है. दस साल के लिए वहां माइनर मिनरल की माइनिंग पर रोक लगा देनी चाहिए. और मास प्लांटेशन की जरुरत है."

पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के 40 एकड़ की एडीजी ने बदली सूरत

ग्वालियर के तिघरा में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल में आईपीएस राजाबाबू सिंह के प्रयासों से तस्वीर बदल गई है. यहां उन्होंने जैव विविधता खो चुकी बंजर भूमि की तस्वीर बदल दी. 172 एकड़ के इस परिसर में 40 एकड़ के हिस्से में पौधे अलग-अलग प्रजातियों के लगाए गए हैं. बाकायदा मेडिशनल प्लांट के साथ एक हर्बल गार्डन भी अलग से बनाया गया है. उन्हें उनके इस प्रयास के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में जैव विविधता दिवस के मौके पर राज्य जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया.

यूपी में थमी हादसों की रफ्तार, सीएम योगी की सख्ती लाई रंग; सड़क दुर्घटनाएं और मौतें 22 प्रतिशत तक हुईं कम

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संजीदगी अब धरातल पर रंग लाने लगी है। प्रदेश में सड़क हादसों को न्यूनतम करने और कीमती जानों को बचाने के लिए चलाए जा रहे चौतरफा अभियानों का बड़ा असर देखने को मिला है। सरकारी पोर्टल 'ई-डीएआर' (e-DAR) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 (जनवरी से अप्रैल) की तुलना में वर्ष 2026 की समान अवधि में सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों में अभूतपूर्व कमी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री के कड़े निदेर्शों के बाद शुरू हुआ यह जागरूकता और सुधार का अभियान अब प्रदेश के सुरक्षित सफर की नई इबारत लिख रहा है।

दुर्घटनाओं और मौतों में 22 प्रतिशत तक की कमी

डिजिटल डेटा के अनुसार, जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच पिछले वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में 3,669 (21 प्रतिशत) की उल्लेखनीय कमी आई है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि सड़क हादसों में जान गंवाने वाले नागरिकों की संख्या में भी 2,212 (22 प्रतिशत) की भारी गिरावट दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री के विजन के अनुरूप परिवहन विभाग पूरे प्रदेश में सघन प्रचार-प्रसार कर रहा है, जिसके तहत

राज्य भर में लगभग 2,000 प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स लगाकर आम जनता को यातायात नियमों के प्रति निरंतर जागरूक किया जा रहा है।

सड़क सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) के चालकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हर छह महीने में चालकों की अनिवार्य स्वास्थ्य और नेत्र जांच की जा रही है, जिसके अंतर्गत अप्रैल 2026 तक 18,975 चालकों का मेडिकल टेस्ट पूरा हो चुका है। इसके अलावा, यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसों पर रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप लगाए गए हैं, चालकों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट अनिवार्य किया गया है और 300 किलोमीटर से अधिक लंबे रूटों की बसों में दो ड्राइवरों की तैनाती को सख्ती से लागू किया गया है।

'जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट' योजना से बचीं 566 जानें

हादसों में होने वाली मृत्यु दर को शून्य पर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की 'जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट' (ZFD) योजना उत्तर प्रदेश में बेहद कारगर साबित हो रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों के 487 क्रिटिकल पुलिस थानों पर इस योजना को लागू किया गया है। यातायात निदेशालय के अनुसार, इन क्रिटिकल थानों के अंतर्गत 573 विशेष 'कॉरिडोर टीमें' गठित की गई हैं, जिनमें 2,865 पुलिसकर्मी दिन-रात मुस्तैद हैं। इसी का नतीजा है कि महज 4 महीनों के भीतर 566 नागरिकों को समय पर सहायता देकर उनकी जान बचाई जा चुकी है।

एक्सप्रेस-वे और हाईवे पर 656 'होल्डिंग एरिया' चिह्नित

सड़क प्रबंधन को नया आयाम देते हुए 1 जनवरी 2026 से 15 मई 2026 के बीच यूपी के सभी 18 मंडलों में सुरक्षित 'होल्डिंग एरिया' चिह्नित कर नोटिफाइड किए गए हैं। प्रदेश भर में कुल 656 होल्डिंग एरिया चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से 630 को आधिकारिक तौर पर नोटिफाइड किया जा चुका है। इसमें सबसे आगे आगरा मंडल रहा है जहाँ सर्वाधिक 121 एरिया चिह्नित किए गए हैं। इसके बाद बरेली में 103, मुरादाबाद में 75 और आजमगढ़ मंडल में 62 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं ताकि यातायात का दबाव बढ़ने या आपात स्थिति में वाहनों को सुरक्षित ढंग से प्रबंधित किया जा सके।

"मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश पर परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर आम नागरिकों को निरंतर जागरूक कर रहा है। सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने की दिशा में अन्य संबंधित विभागों के साथ मिलकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हम आम नागरिकों से भी अपील करते हैं कि वे हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करें। बहुत जल्द सड़क सुरक्षा और स्कूली वाहनों की फिटनेस को लेकर प्रदेश व्यापी अभियान दोबारा शुरू किया जाएगा।" - **आशुतोष निरंजन, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश**

योगी सरकार की सोलर दीदी योजना ₹14,196 वेतन और मुफ्त सोलर प्लांट से महिलाओं को मिल रही आत्मनिर्भरता

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाओं को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जनपद वाराणसी एक नई पहचान बना रहा है.वाराणसी की महिलाएं सोलर लीडर बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहीं हैं. सोलर दीदी पहल के माध्यम से महिलाओं को न केवल तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें रोजगार, सम्मान और ऊर्जा स्वावलंबन से भी जोड़ा जा रहा है. प्रमुख सोलर कंपनियों द्वारा यूपी नेडा को दिए गए प्रस्ताव के अनुसार चयनित सोलर दीदियों को वाराणसी में रहकर कार्य करने का अवसर मिलेगा.

इस संबंध में यूपी नेडा डायरेक्टर रविन्दर सिंह ने बताया कि यूपीनेडा इम्पेनल्ड वेंडर्स द्वारा महिलाओं को ₹14,196 प्रति माह का वेतन दिया जाता है. इसके साथ ही वेंडर्स द्वारा प्रत्येक सोलर दीदी को लगभग ₹1.30 लाख मूल्य का 2 किलोवाट सोलर प्लांट निःशुल्क दिया जाएगा, जिससे वे अपने घर को सौर ऊर्जा से जोड़ सकेंगी.

वाराणसी की सोलर दीदियां बनीं प्रेरणा का नया मॉडल

महिलाओं को आधुनिक ऊर्जा उपयोग से जोड़ने हेतु एक इंडक्शन स्टोव भी वेंडर्स द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा. इसके अतिरिक्त भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा प्रत्येक सफल सोलर स्थापना पर ₹1000 की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाएगी. विभाग की ओर से सभी प्रशिक्षुओं से अपील की गई है कि वे समय से प्रशिक्षण केंद्र पहुंचें, सात दिवसीय प्रशिक्षण को गंभीरता से पूरा करें तथा टेस्ट उत्तीर्ण कर इस अभियान का हिस्सा बनें. यह पहल केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि महिलाओं को ऊर्जा क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.वाराणसी में चल रही यह पहल अब पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बनती दिखाई दे रही है, जहां महिलाएं सोलर दीदी बनकर हरित ऊर्जा क्रांति की अगुवाई कर रही हैं.

प्रदेश में अब तक 5,44,810 से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित

उत्तर प्रदेश में अब तक 5,44,810 से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं. राज्य में कुल 9,68,548 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से बड़े पैमाने पर स्वीकृति एवं स्थापना सुनिश्चित की गई है. इसके साथ ही प्रदेश में 1,844.87 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता सृजित हुई है तथा ₹3,539.06 करोड़ की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा एवं ₹1200 करोड़ से अधिक की सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा जारी की जा चुकी है. प्रदेश में प्रतिदिन 82 लाख यूनिट से अधिक मुफ्त बिजली रूफटॉप सोलर के माध्यम से उत्पन्न हो रही है, जिसकी अनुमानित लागत 5 करोड़ रुपये से अधिक है.

भाजपा में आते ही राघव चड्ढा को मिला बड़ा इनाम, राज्यसभा में मिली अहम जिम्मेदारी, बदली सियासी तस्वीर

(जीएनएस)।

आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राघव चड्ढा को अब राज्यसभा में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। उन्हें राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने अअढ के कई सांसदों के साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था।

राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने समिति का पुनर्गठन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि बीजेपी ने

राघव चड्ढा को सिर्फ पार्टी में शामिल नहीं किया, बल्कि तुरंत एक अहम संसदीय भूमिका भी सौंप दी।

राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि 20 मई से प्रभावी नई याचिका समिति का गठन किया गया है। इस समिति में कुल 10 सदस्यों को शामिल किया गया है और राघव चड्ढा को इसका चेयरमैन बनाया गया है।

यह समिति संसद की उन महत्वपूर्ण समितियों में मानी जाती है, जो सीधे जनता की शिकायतों और जनहित से जुड़े मामलों की जांच करती हैं। यानी अब राघव चड्ढा की भूमिका सिर्फ सांसद तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वह सार्वजनिक शिकायतों और प्रशासनिक मामलों पर भी नजर रखेंगे।

याचिका समिति आखिर करती क्या है?

राज्यसभा की याचिका समिति का मुख्य काम सदन में आने वाली याचिकाओं की जांच करना होता है। अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसकी शिकायत सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से हल नहीं हो रही, तो वह इस समिति के जरिए अपनी बात संसद तक पहुंचा सकता है।

यह समिति जनहित से जुड़े मुद्दों, सरकारी कामकाज और प्रशासनिक फैसलों की भी समीक्षा करती है। आसान भाषा में समझें तो यह जनता और संसद के बीच एक औपचारिक पुल की तरह काम करती है। इसी वजह से इस समिति का अध्यक्ष बनना सिर्फ औपचारिक पद नहीं माना जाता, बल्कि इसे राजनीतिक भरोसे और संसदीय प्रभाव से जोड़कर देखा जाता है।

राघव चड्ढा की अध्यक्षता वाली इस समिति में कई अन्य सांसदों को भी सदस्य बनाया गया है। इनमें: हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंक कुमार नायक, मस्थान राव यादव बीधा, जेबी मेथेर हिशाम, सुभाशीष खुंटिया, रवंगवरा नारजारी, संतोष कुमार जैसे नाम शामिल हैं।

राज्यसभा सचिवालय की अधिसूचना के बाद यह समिति तुरंत प्रभाव से काम शुरू करेगी।

राघव चड्ढा पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद चुने गए थे। लेकिन 24 अप्रैल 2026 को उन्होंने पार्टी छोड़ दी। खास बात यह रही कि वह अकेले नहीं गए, बल्कि अअढ के दो-तिहाई से ज्यादा राज्यसभा सांसदों को साथ लेकर बीजेपी में शामिल हुए।

उनके साथ हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, विक्रमजीत साहनी और राजेंद्र गुप्ता जैसे नेता भी बीजेपी में आए। उस समय राघव चड्ढा ने कहा था कि उन्हें महसूस होने लगा था कि वह "गलत पार्टी में सही आदमी" हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी अब अपने मूल सिद्धांतों और नैतिकता से भटक चुकी है।

राघव चड्ढा ने अअढ पर क्या आरोप लगाए थे?

बीजेपी में शामिल होते वक्त राघव चड्ढा ने कहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 15 साल अअढ को दिए, लेकिन अब पार्टी देशहित की जगह निजी राजनीतिक फायदे के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि संविधान के प्रावधानों के तहत उन्होंने अपने समूह का बीजेपी में विलय करने का फैसला लिया। इस बयान के बाद देशभर की राजनीति में हलचल मच गई थी, क्योंकि राघव चड्ढा को कभी अरविंद केजरीवाल की टीम का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जाता था।

राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी दूसरी अधिसूचना में बताया गया कि मेनका गुरुस्वामी को 'कॉपोर्रेट कानून (संशोधन) विधेयक 2026' पर बनी संयुक्त समिति का सदस्य नामित किया गया है।

बिजनौर में गंगा की धारा को पौराणिक घाट तक लाने की उठी मांग, उट से मिले पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह

(जीएनएस)।

बिजनौर। पूर्व सांसद बिजनौर भारतेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने गंगा की धारा को पौराणिक घाट तक लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने आदि की मांग की।

पूर्व सांसद ने मुख्यमंत्री से दारा नगर गंज क्षेत्र में मां गंगा की धारा को पौराणिक घाट तक लाने की मांग को प्रमुखता से रखा। जिससे क्षेत्र की धार्मिक आस्था, पर्यटन और स्थानीय विकास को नई दिशा मिल सकेगी। साथ ही मंडल स्तर पर बनने वाले स्पोर्ट्स कांप्लेक्स को बिजनौर में बनाए जाने की मांग भी रखी गई। ताकि जनपद के युवाओं और ग्रामीण प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं एवं अवसर प्राप्त हो सकें।

किसानों और पशुपालकों की समस्या को उठाते हुए यह विषय भी रखा कि पशुओं के लिए उपयोग होने वाला भूसा बड़ी मात्रा में पेपर मिलों में जा रहा है। जिसके कारण किसानों को महंगे दामों पर भूसा खरीदना पड़ रहा है।

इस पर भी गंभीरता से रोक लगाने की मांग को भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। पूर्व सांसद ने बताया कि इसके अतिरिक्त बिजनौर के वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर भी

चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी विषयों को गंभीरता से सुना और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

रामगंगा नदी तट पर पर्यटन को विकसित करने और अराजक तत्वों पर रोक की मांग

अफजलगढ़ : ग्राम पंचायत इस्लामनगर व पुराना कालागढ़ रामगंगा नदी तट प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की संभावनाओं से भरपूर क्षेत्र है। लेकिन यहां पर्याप्त व्यवस्थाओं और स्पष्ट दिशा-निदेर्शों के अभाव में अव्यवस्था लगातार बढ़ रही है।

नदी किनारे कुछ अराजक तत्वों द्वारा शराब सेवन, गंदगी फैलाने और असामाजिक गतिविधियों जैसी घटनाएं क्षेत्र की छवि को खराब कर रही हैं। इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों में असंतोष बढ़ रहा है। श्री रामगंगा फाउंडेशन ने प्रशासन से मांग की कि रामगंगा नदी तट पर पर्यटन को व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाए।

यह भी पढ़ें- श्क्लएडः गायों को गर्मी से राहत देने का अनोखा तरीकाः गोशाला में पिलाया गुलाब शर्बत, खिलाए जा रहे मौसमी फल और सब्जियां

इसके तहत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, साफ-सफाई सुनिश्चित करने, चेतावनी बोर्ड लगाने, पुलिस गश्त बढ़ाने तथा पर्यटकों के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित करने जैसे कदम उठाए जाएं। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने वालों में फाउंडर विनोद धारियावाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक सिरोही, विपिन यादव आदि शामिल रहे।

अमेठी की बिजली व्यवस्था पर सांसद किशोरी लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की

अमेठी, कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अमेठी संसदीय क्षेत्र की चरमराई विद्युत व्यवस्था में तत्काल सुधार की मांग की है।

सांसद शर्मा ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री को यह पत्र लिखा, जिसे शनिवार को पत्रकारों के साथ साझा किया गया।

अमेठी के लोगों का आरोप है कि भीषण गर्मी और लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से क्षेत्र की जनता परेशान है। यह मुद्दा अब राजनीतिक स्तर पर भी तूल पकड़ने लगा है।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में शर्मा ने कहा कि भीषण गर्मी के बीच पिछले कई दिनों से अमेठी क्षेत्र में लगातार अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे किसानों, छात्रों, व्यापारियों और आम नागरिकों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

उन्होंने कहा कि रात में बार-बार बिजली जाने से लोगों की दिनचर्या बाधित हो रही है, जबकि सिंचाई प्रभावित होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है।

अमेठी के सांसद ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उमस भरी गर्मी में छोटे बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

शर्मा ने मांग की कि अमेठी में विद्युत आपूर्ति तत्काल सुचारु कराई जाए और अनावश्यक बिजली कटौती पर रोक लगाई जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके।